न्यायाधीश **अजय कुमार मित्तल** *और* **गुर सिंह संधावालिया** *के समक्ष*

मैसर्स ए-वन मेगा मार्ट पी लिमिटेड और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

एचडीएफसी बैंक और अन्य-प्रतिवादी

2012* की सीडब्ल्यूपी संख्या *2250

14 सितंबर, 2012

भारत का संविधान, *1950* - कला*%26 & 227*- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति का प्रवर्तन^ ब्याज अधिनियम, *2002* - धारा *13 (2), 13 (4), 13 (13) & 34* - निजी बैंक के खिलाफ रिट याचिका की रखरखाव^ - याचिकाकर्ता होजरी वस्तुओं आदि के व्यापार के व्यवसाय में लगा हुआ है। - सरफेसी अधिनियम की धारा *13 (2)* और *13 (4)* के तहत बैंक द्वारा शुरू की गई डिफ़ॉल्ट कार्यवाही के कारण - बैंक द्वारा अनुमोदित वन टाइम सेटलमेंट स्कीम - याचिकाकर्ता का पालन करने में विफल रहना ओटीएस के साथ - विस्तार के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया - उसे चुनौती - क्या निजी बैंक के खिलाफ एक रिट याचिका सुनवाई योग्य है - माना जाता है, आमतौर पर कोई रिट निजी बैंक के खिलाफ नहीं होगी - लेकिन जहां अनुसूचित बैंक जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, *1949* के प्रावधानों द्वारा शासित है, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम *2002* के प्रावधानों का सहारा लेता है, यह रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी होगा।

माना जाता है, कि याचिका में मुद्दा इस बात से संबंधित नहीं है कि क्या प्रतिवादी-बैंक आर्टिक्लक में परिभाषित "राज्य" के अर्थ के भीतर आता है

संविधान का 12 या राज्य का एक साधन है या नहीं। सवाल यह है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर "किसी भी व्यक्ति" के खिलाफ विचार किया जा सकता है, जो प्रदर्शन करने के लिए वैधानिक दायित्व के तहत है, जहां दावा की गई राहत आवश्यक रूप से "राज्य", "सरकार" या "प्राधिकरण" या "राज्य के साधन" के खिलाफ नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रागा टूल्स कॉरपोरेशन बनाम श्री सीवी इमैनुअल और अन्य, एआईआर 1969 सुप्रीम कोर्ट 1306 में निर्धारित किया था कि रिट याचिका किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के खिलाफ सक्षम होगी जिस पर वैधानिक कर्तव्य लगाया गया है।

(पैरा 17)

आगे कहा गया कि एक अन्य कारक जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत, बैंक की कार्रवाई के खिलाफ ऋण वसूली न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है और इसके तहत पारित किसी भी आदेश के खिलाफ, उक्त अधिनियम की धारा 18 के तहत ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) में अपील सुनवाई योग्य है। DRAT द्वारा पारित आदेश उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है। इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित मुद्दे को तय करने में सरफेसी अधिनियम की धारा 34 का भी महत्व है। यह पहलू यहां उठाए गए विवाद को अलग आयाम देता है। धारा 34 उन कार्रवाइयों से संबंधित मामलों में सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है जहां एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है। संविधान समानता की गारंटी देता है और किसी प्राधिकरण की किसी भी मनमानी कार्रवाई के खिलाफ हमला करता है यह नहीं कहा जा सकता है कि जहां भी कोई प्राधिकरण भेदभावपूर्ण या अनुचित तरीके से कार्य करता है, पीड़ित पक्ष सिविल सूट के माध्यम से या उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करके किसी भी उपाय के बिना होगा। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता है कि अनुसूचित बैंक द्वारा एक कार्रवाई, जिस पर सरफेसी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं और इसके द्वारा लागू किए गए हैं, यह इस न्यायालय के असाधारण रिट क्षेत्राधिकार से प्रतिरक्षा होगी।

(पैरा 26)

आगे कहा गया कि उपरोक्त से, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आमतौर पर कोई भी रिट निजी बैंक के खिलाफ नहीं होगी। हालांकि, जहां बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत एक अनुसूचित बैंक है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों द्वारा शासित है, यह इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी होगा जहां अनुसूचित बैंक सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेता है।

(पैरा 28)

अमोल रतन सिद्धू, सीनियर एडवोकेट के साथ रोहित सूरी, एडवोकेट, **याचिकाकर्ताओं के लिए।**

राधिका सूरी, एचओ ईसी बैंक की एडवोकेट।

अजय कुमार मित्तल, जे.

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर इस याचिका में, क्रमशः दिनांक 27.5.2011 और 24.8.2011 के आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसमें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, "SARFAESI अधिनियम") को अस्वीकार कर दिया गया है।

(2) संक्षेप में, याचिका में वर्णित विवाद के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। कंपनी होजरी आइटम, रेडीमेड गैनेंट और संबंधित वस्तुओं के व्यापार के व्यवसाय में लगी हुई है। प्रतिवादी-बैंक की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए याचिका कंपनी की चूक और असमर्थता के कारण, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) और 13 (4) के तहत बैंक द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें बंधक संपत्तियों और बंधक वस्तुओं को बेचने का प्रस्ताव किया गया था। याचिकाकर्ता कंपनी ने गिरवी रखी गई संपत्तियों को बेचने का प्रस्ताव रखा ताकि उसी की सर्वोत्तम कीमत प्राप्त की जा सके और बैंक को भुगतान किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए, याचिकाकर्ता कंपनी ने वन टाइम सेटलमेंट एससीएमसीसी (ओटीएस) के तहत ऋण सुविधा के निपटान के लिए बैंक से संपर्क किया। कंपनी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25-3-2010 के प्रस्ताव की प्रति याचिका के साथ अनुबंध-आरआई में दी गई है। उक्त प्रस्ताव को बैंक के दिनांक 22.01.2011 के पत्र द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया। बैंक ने याचिकाकर्ता-कंपनी को कथित बंधक संपत्तियों को 250 लाख रुपये की कुल बिक्री प्रतिफल के लिए बेचने के लिए जुर्माना दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता-कंपनी ने संपत्ति की बिक्री के लिए एक समझौता किया। इसने समझौते की शर्तों के रूप में 50 लाख रुपए जमा कराए परंतु 22-3-2011 तक शेष 200 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा। उन्होंने कहा, 'याचिकाकर्ता-कंपनी ने बैंक से समय बढ़ाने की मांग की। इस बीच, याचिकाकर्ता नंबर 2 और 3 के पिता की मृत्यु हो गई और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, शेष राशि की व्यवस्था समय पर नहीं की जा सकी। बैंक ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दी गई एकबारगी निपटान योजना को वापस ले लिया। 1 आईसीएनसीसी यह याचिका।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत पारित आक्षेपित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के लिए कोई उपाय उपलब्ध नहीं था क्योंकि धारा 34 सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है और ऐसी स्थिति में, रिट एकमात्र उपाय था। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी-बैंक द्वारा संपत्ति को जारी करने के लिए देयता का निर्वहन करने की अनुमति दी गई अवधि का पालन याचिकाकर्ताओं के नियंत्रण से परे कुछ परिस्थितियों के कारण नहीं किया जा सकता है। तर्क को विस्तृत करते हुए, यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 के पिता जो कंपनी के प्रबंध निदेशक थे, 17.6.2011 को समाप्त हो गए थे और इसलिए, याचिकाकर्ता-कंपनी समय अनुसूची का पालन करने में सक्षम नहीं थी। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता-कंपनी के आवेदन को स्वीकार करने के लिए बैंक पर वैधानिक दायित्व था। एक बार जब कोई दुर्भावना नहीं थी और रेडरसेल का कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं था, तो याचिकाकर्ता-कंपनी इस न्यायालय के समक्ष है। गुण-दोष के आधार पर संबोधित करते हुए, यह तर्क दिया गया था कि इस रिटयाचिका में बैंक की कार्रवाई की तर्कसंगतता और निष्पक्षता को चुनौती दी गई थी क्योंकि बैंक बकाया देयता के निर्वहन के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज करने में बहुत कठोर था। देरी को माफ करने और राशि स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद थे। यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ताओं ने 26.7.2011 को शेष 2 करोड़ रुपये की राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे बैंक द्वारा मूल निपटान के संदर्भ में भुगतान किया जाना था। उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ताओं के लिए 25.7.2012 को उच्च न्यायालय में पहले से जमा किए गए 2 करोड़ रुपये के अलावा 50,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने में याचिकाकर्ताओं की इच्छा दिखाई थी। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इस स्थिति में, याचिकाकर्ता-कंपनी की सदाशयता स्पष्ट थी। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया: -

(1) **सत कर तार आइस एंड जनरल मिल्स बनाम पंजाब फाइनेंशियल**

निगम *(1)*।

(2) **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम विजय कुमार *(2)*।**

(3) **श्रीमती पेरियाक्कल एवं अन्य क्रियाएं श्रीमती दक्षिनी *(3)*।**

---

(1) 2008(1) आईएसजे (बैंकिंग) 248 (पी एंड एच)
(2) (2007)11 एससीसी 369
(3) (1983) 2 एससीसी 127

(4) ***(4)*** **मैसर्स सरदार एसोसिएट्स और अन्य बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक एवं अन्य।**

(5) **यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और अन्य *(5)*।**

(6) **फेडरल बैंक लिमिटेड वर्मसागर थॉमस और अन्य**
(6) .

(7) **पंजाब एंड सिंध बैंक बनाम ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य *(7)*।**

(vi) **मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ *(8)*।**

(9) **आईसीआईसीआई बैंक बनाम शांति देवी शर्मा और अन्य *(9)*।**

(4) प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने **फेडरल बैंक लिमिटेड**^ मामले (सुप्रा) के फैसले के मद्देनजर प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि निजी बैंक के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। विलंब और विलंब के संबंध में एक अन्य प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी और रिट याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना की गई थी। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की दलीलों का खंडन करते हुए, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने 6.6.2009 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत जारी नोटिस के खिलाफ अधिनियम की धारा 13 (3 ए) के तहत आपत्तियां दर्ज करने के वैधानिक उपाय का लाभ नहीं उठाया और इस प्रकार, इसे माफ कर दिया गया। सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील का आगे का उपाय सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत जारी नोटिस के खिलाफ सुनवाई योग्य था।

(5) गुण-दोष के आधार पर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि मूल रूप से दी गई पेनिशन सशर्त अनुमति थी जिसे 22.3.2011 तक संपूर्ण बिक्री प्रतिफल जमा करने पर ही प्रभावी होना था जिसे बाद में दिनांक 18.4.2011 के पत्र द्वारा बढ़ा दिया गया था। याचिकाकर्ता इसका सम्मान करने में विफल रहे हैं, अब रिट क्षेत्राधिकार की आड़ में किसी भी राहत का दावा नहीं कर सकते हैं। यह भी था (4) (2009) 8 एससीसी 257 (5) (2010)8 एससीसी 110

(6) (2003) 10 एससीसी 733
(7) 200 8(1) पीएलआर 203 (पी एंड एच)
(8) (2004)4 एससीसी 311
(9) (2008) 7 एससीसी 532

प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत देय पूरी राशि का निर्वहन करके संपत्ति को भुनाने का अधिकार था स्त्री-विषयक बैंक को। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

/ **फेडरल बैंक लिमिटेड केस *(सुप्रा)* और सत्यवती टंडन की मामला**

(सुप्रा) और मद्रास उच्च न्यायालय में **तमिलनाडु औद्योगिक निवेश** (v) चेन्नई मिलेनियम बिजनेस सोल्यूशन प्रा लि। **सीमित और दूसरा,** एआईआर 2005 मद्रास 232 उनके प्रस्तुतीकरण के समर्थन में। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी भी वैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया था और *

इसलिए, कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सका।

(6) हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(7) 'I'he आवश्यक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए, उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है: -

(1) क्या वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी नंबर 1 -बैंक के खिलाफ सक्षम है? ;

(2) क्या रिट याचिका में विलंब और कुंडी है और *r* अकेले उस आधार पर खारिज होने के लायक हैं ?;

(3) क्या याचिकाकर्ताओं ने सदाशयता से काम किया है और राहत के हकदार हैं जैसा कि रिट याचिका में दावा किया गया है?

(8) रिट याचिका की विचारणीयता से संबंधित मुद्दे (ए) की जांच करना **k** प्रतिवादी नंबर 1 -बैंक के खिलाफ, अनिवार्य रूप से कुछ के लिए संदर्भ दिया जाता है

माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित पूर्वोदाहरणों में प्रतिपादित प्रासंगिक संविधियों और सिद्धांतों के उपबंध भी लागू किए गए हैं।

(9) सबसे पहले, यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक सांविधिक प्राधिकरण है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 (ई) * (संक्षिप्तता के लिए, '1934 अधिनियम') "अनुसूची बैंक" का अर्थ बैंक के रूप में वर्णित करता है

दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। 1934 के अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी-एचडी एफसी बैंक लिमिटेड उसमें निर्दिष्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक एक सांविधिक प्राधिकरण होने के नाते अनुसूचित बैंकों के कार्यकरण के मामले में पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करता है। के लिए * उपर्युक्त उद्देश्य के अनुसार, रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश जारी करने का पात्र है समय-समय पर।

(10) संसद ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (संक्षेप में, '1949 अधिनियम') को बैंकिंग से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया। 1949 अधिनियम की धारा 5 (1) "रिज़र्व बैंक" को 1934 अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक के रूप में परिभाषित करती है। के कारण[1]
1949 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार रिज़र्व बैंक को अनुसूचित बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने का अधिकार है।

(11) 1949 अधिनियम की धारा 21 रिज़र्व बैंक को बैंकिंग कंपनियों द्वारा अग्रिमों को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत करती है। इसकी धारा 21 निम्नानुसार है:

"21. बैंकिंग कंपनियों द्वारा अग्रिमों को नियंत्रित करने की रिज़र्व बैंक की शक्ति -(1) यदि रिज़र्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोक हित में या जमाकर्ताओं के हित में या बैंकिंग

नीति में आवश्यक या समीचीन है तो वह बैंकिंग कंपनियों द्वारा सामान्यतया या किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा विशेष रूप से अनुसरण किए जाने वाले अग्रिमों के संबंध में नीति अवधारित कर सकेगा, और जब नीति इस प्रकार निर्धारित की गई है, तो सभी बैंकिंग कंपनियां या संबंधित बैंकिंग कंपनी, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार निर्धारित नीति का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिज़र्व बैंक में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिज़र्व बैंक ^
बैंकिंग कंपनियों, सामान्यतः या किसी बैंकिंग कंपनी या विशेष रूप से बैंकिंग कंपनियों के समूह को निदेश देना, जो कि-

(1) उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए अग्रिम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है,

(2) सुरक्षित के संबंध में बनाए रखा जाने वाला मार्जिन J
अग्रिम

(3) अग्रिम या अन्य वित्तीय आवास की अधिकतम राशि, जो एक बैंकिंग कंपनी की चुकता पूंजी, भंडार और जमा और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, उसके द्वारा बनाई जा सकती है *
किसी एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों या व्यक्ति के संघ को बैंकिंग कंपनी,

(4) अधिकतम राशि, खंड (सी) में निर्दिष्ट विचारों को ध्यान में रखते हुए, किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा किसी एक की ओर से गारंटी दी जा सकती है *
कंपनी, फर्म, व्यक्तियों या व्यक्तियों का संघ, और

(5) ब्याज दर और अन्य शर्तें जिन पर अग्रिम या अन्य वित्तीय समायोजन किए जा सकते हैं या गारंटी दी जा सकती हैं।

(3) प्रत्येक बैंकिंग कंपनी इस धारा के तहत उसे दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

(12) उपर्युक्त उपबंध का अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी नीतियां बनाने का अधिकार है जिनका पालन करने के लिए बैंकिंग कंपनियां बाध्य हैं। 1949 के अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक बैंकिंग कंपनी उसके संदर्भ में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी। 1949 अधिनियम की धारा 35A, जिसे बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, रिज़र्व बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग नीति के हित में निदेश जारी करने का अधिकार देती है।

(13) 1949 अधिनियम की धारा 36 भी भारतीय रिज़र्व बैंक की आगे की शक्तियों और कार्यों के लिए प्रदान करती है, उप-धारा (1) का खंड (डी) जिसके तहत निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

(14) रिज़र्व बैंक की आगे की शक्तियाँ और कार्य - (1) रिज़र्व बैंक-

(क) *** ***

(ख) * * * ++* * * *

(ग) * * * $♦+ +++

W) किसी भी समय, यदि यह संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में या बैंकिंग नीति के हित में या बैंकिंग कंपनी के मामलों को रोकने के लिए टीएचसी बैंकिंग कंपनी या उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से आयोजित किया जा रहा है, तो ऐसा करना आवश्यक है, लिखित रूप में आदेश द्वारा और ऐसे नियमों और शर्तों पर जो एसपीसीसीआई जीईडी हो सकते हैं-

(1) बैंकिंग कंपनी से यह अपेक्षा करना कि वह बैंकिंग कंपनी के मामलों से संबंधित या उससे उत्पन्न किसी मामले पर विचार करने के उद्देश्य से अपने निदेशकों की बैठक बुलाए; या बैंकिंग कंपनी के किसी अधिकारी से रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी के साथ ऐसे किसी मामले पर चर्चा करने के लिए अपेक्षा करना;

(2) अपने एक या अधिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करना, जिनके लिए बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल या किसी समिति या उसके द्वारा गठित किसी अन्य निकाय की किसी बैठक में कार्यवाही; बैंकिंग कंपनी से अपेक्षा करती है कि वह इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारियों को ऐसी बैठकों में सुनवाई का अवसर दे और ऐसे अधिकारियों से यह भी अपेक्षा करे कि वे ऐसी कार्यवाहियों की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को भेजें;

(3) बैंकिंग कंपनी या उसके द्वारा गठित किसी समिति या उसके द्वारा गठित किसी अन्य निकाय के निदेशक मंडल से अपेक्षा करता है कि वह इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को अपने सामान्य पते पर बोर्ड, समिति या उसके द्वारा गठित अन्य निकाय की किसी बैठक की सभी सूचनाएं और उससे संबंधित अन्य संचार लिखित रूप में दे;

(4) बैंकिंग कंपनी या उसके कार्यालयों या शाखाओं के कार्यों का संचालन करने के तरीके का निरीक्षण करने के लिए अपने एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त करें और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करें;

(5) बैंकिंग कंपनी को इस तरह के भीतर बनाने की आवश्यकता है
समय जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, प्रबंधन में ऐसे परिवर्तन जो रिज़र्व बैंक आवश्यक कर सकता है। ''

(14) संसद ने बैंककारी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1959 द्वारा अधिनियम में धारा 36क को अंतःस्थापित किया जिसके अनुसार 1949 के अधिनियम के उपबंधों को कतिपय बैंकिंग कंपनियों पर लागू नहीं किया जाना था।

(15) अब हम बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (संक्षेप में डीआरए सी एफ) अधिनियम के उपबंधों की जांच और विश्लेषण कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए विशेष मशीनरी के निर्माण को सुगम बनाने का प्राथमिक उद्देश्य। टीएचसी डीआरटी अधिनियम में बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए आवेदनों का संक्षिप्त अधिनिर्णय करने तथा निर्धारित राशि की वसूली के तरीकों को विनिदष्ट करने के लिए क्षेत्राधिकार और शक्तियों तथा प्राधिकार के साथ अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान है

ट्रिब्यूनल या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा। यह धारा 17 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर भी रोक लगाता है। अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों को सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित विस्तृत प्रक्रिया से भी मुक्त कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, डीआरटी अधिनियम ने न केवल बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाये की त्वरित वसूली के लिए विशेष प्रक्रियात्मक तंत्र अस्तित्व में लाया है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान किया है कि चूककर्ता उधारकर्ता बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को विफल करने के लिए सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

(16) संविधि के विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद सरफेसी अधिनियम की योजना

को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन (10) के मामले** में निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में चुना गया है: -

"3. सरफेसिया अधिनियम की धारा 13 में सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए विस्तृत तंत्र शामिल है। इसकी उपधारा (1) में कहा गया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 69 या 69-ए में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में सृजित किसी प्रतिभूति हित को न्यायालय या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे लेनदार द्वारा लागू किया जा सकता है। धारा 13 की उपधारा (2) सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा उठाए जाने वाले कई कदमों में से सबसे पहले बताती है सूद। इस उप-धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई उधारकर्ता, जो किसी सुरक्षित लेनदार के दायित्व के अधीन है, प्रतिभूत ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक करता है और ऐसे ऋण के संबंध में उसके खाते को अनुपयोज्य परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो प्रतिभूत ऋणदाता को नोटिस की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपनी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए लिखित रूप में नोटिस द्वारा उधारकर्ता से यह अपेक्षा कर सकता है कि यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, सुरक्षित लेनदार धारा 13 (4) के संदर्भ में अपने सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा। धारा 13 की उपधारा (3) में कहा गया है कि धारा 13 (2) के तहत जारी किए गए नोटिस में उधारकर्ता द्वारा देय राशि का विवरण और साथ ही सुरक्षित संपत्ति का विवरण होगा

(10) एआईआर 2010 एससी 3413

बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा लागू किया जाना। धारा 13 की उपधारा (3-ए) में कहा गया है कि उधारकर्ता धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के जवाब में अभ्यावेदन दे सकता है और अपने खाते को अनुपयोज्य परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने के साथ-साथ नोटिस में निर्दिष्ट राशि की मात्रा को भी चुनौती दे सकता है। यदि बैंक या वित्तीय संस्था इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उधारकर्ता का पंजीकरण/निषेध स्वीकार्य नहीं है, तो एक सप्ताह के भीतर अभियोग न करने के कारणों को सूचित करना आवश्यक है। धारा 13 की उप-धारा (4) एसपीसीसीआई विभिन्न तरीकों को अपनाती है जिन्हें सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा अपनाया जा सकता है। प्रतिभूत ऋणदाता ऋणकर्ता की प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले सकता है तथा उसे पट्टा, समनुदेशन अथवा बिक्री के माध्यम से प्रतिभूत आस्तियों की वसूली के लिए अंतरित कर सकता है। 'यह शर्त है कि पट्टे आदि के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग केवल वहीं किया जाएगा जहां उधारकर्ता के कारोबार का पर्याप्त हिस्सा sccurcddcbt के रूप में रखा जाता है। यदि व्यवसाय के किसी भी हिस्से का प्रबंधन पृथक्करणीय है, तो सुरक्षित लेनदार केवल उधारकर्ता के ऐसे व्यवसाय का प्रबंधन ले सकता है जो सुरक्षा से संबंधित है। सुरक्षित लेनदार किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त कर सकता है, जिसका कब्जा ले लिया गया है। सुरक्षित लेनदार, लिखित रूप में नोटिस द्वारा, उस व्यक्ति को भी बुला सकता है जिसने उधारकर्ता से किसी भी सुरक्षित संपत्ति का अधिग्रहण किया है, पैसे का भुगतान करने के

लिए, जो उधारकर्ता की 1 देयता का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। धारा 13 की उपधारा (7) में कहा गया है कि जहां उपधारा (4) के तहत ^उधारकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, वहां सुरक्षित लेनदार द्वारा उचित रूप से किए गए सभी लागत, प्रभार और व्यय या उसके आनुषंगिक किसी भी व्यय को उधारकर्ता से वसूल किया जा सकता है। 'सुरक्षित लेनदार द्वारा प्राप्त की गई एकमात्र धनराशि को उसके द्वारा ट्रस्ट में रखा जाना आवश्यक है और पहले उदाहरण में, ऐसी लागतों, शुल्कों और खर्चों के लिए और फिर सुरक्षित लेनदार के बकाया के निर्वहन में लागू किया जाता है। धन का अवशेष उस हकदार व्यक्ति को उसके अधिकारों और हित के अनुसार देय है। धारा 13 की उप-धारा (8) सुरक्षित संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है यदि लागत, शुल्क और व्यय के साथ सुरक्षित crcditortogethcr के कारण राशि

उसके द्वारा किए गए खर्च को ऐसी बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित समय से पहले किसी भी समय निविदा दी जाती है। धारा 13 की उपधारा (9) उस स्थिति से संबंधित है जिसमें एक से अधिक सुरक्षित लेनदारों की सुरक्षित परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी है और यह निर्धारित करता है कि एक से अधिक सुरक्षित लेनदारों द्वारा वित्तीय संपत्ति के वित्तपोषण या सुरक्षित लेनदारों द्वारा वित्तीय संपत्ति के संयुक्त वित्तपोषण के मामले में, कोई भी व्यक्तिगत सुरक्षित लेनदार उप-धारा (4) के तहत किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वे सभी इस तरह के लिए सहमत न हों गमन। धारा 13(9) के पांच असंख्य परंतुक हैं जो परिसमापन में किसी कंपनी के कामगारों के समरूप प्रभार से संबंधित हैं। इनमें से पहला परन्तुक यह निर्धारित करता है कि परिसमापन में किसी कंपनी के मामले में, प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529-क के उपबंधों के अनुसार वितरित किया जाएगा। दूसरा परंतुक इस अधिनियम के लागू होने पर या उसके बाद बंद होने वाली कंपनी के मामले से संबंधित है। यदि ऐसी कंपनी का सुरक्षित लेनदार कंपनी अधिनियम की धारा 529 (1) के तहत अपने ऋण को त्यागने और साबित करने के बजाय अपनी सुरक्षा का एहसास करने का विकल्प चुनता है, तो वह धारा 529-ए के अनुसार परिसमापक के पास कामगारों की बकाया राशि जमा करने के बाद बिक्री आय को बनाए रख सकता है। तीसरे परंतुक में परिसमापक से अपेक्षा की गई है कि वह धारा 529-क के अनुसार कामगारों को देय देय राशियों के बारे में प्रतिभूत ऋणदाता को सूचित करे। यदि कामगारों को देय राशि निश्चित नहीं है तो परिसमापक को अनुमानित राशि की सूचना सुरक्षित ऋणदाता को देनी होगी । चौथा परंतुक यह निर्धारित करता है कि यदि प्रतिभूत ऋणदाता कामगारों की देय राशियों की अनुमानित राशि जमा करता है तो ऐसा लेनदार कामगारों की शेष राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा अथवा परिसमापक के पास जमा की गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, प्राप्त करने का हकदार होगा। पांचवें परंतुक के अनुसार, प्रतिभूत ऋणदाता से यह अपेक्षित है कि वह परिसमापक को कर्मकारों की शेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करने का वचन दे। धारा 13 की उपधारा (10) में कहा गया है कि जहां सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री आय से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, सुरक्षित लेनदार उधारकर्ता से शेष राशि की वसूली के लिए धारा 17 के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है।

उप-धारा (11) में कहा गया है कि इस धारा के तहत या उसके द्वारा सुरक्षित लेनदार को प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह गारंटीकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने या प्रतिभूत परिसंपत्तियों को बेचने का हकदार होगा, जो कि खंड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट उपायों का सहारा लिए बिना सुरक्षित संपत्ति के संबंध में उप-धारा (4) का। धारा 13 की उपधारा (12) में यह निर्धारित किया गया है कि अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता को उपलब्ध अधिकारों का प्रयोग इस निमित्त प्राधिकृत उसके एक या अधिक अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। उपधारा (13) में कहा गया है कि उपधारा (2) के तहत नोटिस प्राप्त होने के बाद, उधारकर्ता बिक्री, पट्टे या अन्यथा (अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना नोटिस में निर्दिष्ट अपनी किसी भी सुरक्षित संपत्ति को स्थानांतरित

नहीं करेगा। धारा 14 के अनुसार, सुरक्षित लेनदार मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में सुरक्षित संपत्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज उसके कब्जे के लिए पाए जाते हैं। यदि ऐसा कोई अनुरोध किया जाता है, तो मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, ऐसी संपत्ति या दस्तावेज को अपने कब्जे में लेने और उसे सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करने के लिए बाध्य है।

4) धारा 17 उधारकर्ता सहित किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध उपायों की बात करती है, जिसे धारा 13 के सुरक्षित लेनदार उप-व्यय (4) द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ शिकायत हो सकती है। ऐसा व्यथित व्यक्ति उस उपधारा के तहत कार्रवाई किए जाने की तारीख से 45 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल को आवेदन कर सकता है। अत्यधिक सावधानी के माध्यम से, धारा 17 (1) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 13 (3-ए) के संदर्भ में उधारकर्ता को कारणों का संचार धारा 17 (1) के तहत आवेदन दायर करने के लिए आधार नहीं होगा। धारा 17 की उपधारा (2) इस बात पर विचार करने के लिए ट्रिब्यूनल पर एक कर्तव्य डालती है कि क्या सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा किए गए उपाय thcAct के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार हैं। यदि अधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करने के पश्चात् अधिकरण की स्थापना की जाती है।

इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सुरक्षित लेनदार द्वारा किए गए उपाय धारा 13 की उपधारा (4) के अनुरूप नहीं हैं, तो यह सुरक्षित लेनदार को व्यवसाय के प्रबंधन या उधारकर्ता को सुरक्षित संपत्ति के कब्जे को बहाल करने का निर्देश दे सकता है। दूसरी ओर, यदि ट्रिब्यूनल पाता है कि धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया गया सहारा अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार है, तो, किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद लागू है, सुरक्षित लेनदार अपने सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए धारा 13 (4) में निर्दिष्ट एक या अधिक उपायों का सहारा ले सकता है। धारा 17 की उपधारा (5) में साठ दिनों की समय-सीमा विहित की गई है जिसके भीतर धारा 17 के अधीन किए गए आवेदन का निपटान किया जाना अपेक्षित है। इस उप-धारा के परंतुक में समय के विस्तार की परिकल्पना की गई है, लेकिन किसी आवेदन के अधिनिर्णय के लिए बाहरी सीमा चार महीने है। यदि ट्रिब्यूनल चार महीने की अधिकतम अवधि के भीतर आवेदन पर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो कोई भी पक्ष ट्रिब्यूनल को शीघ्रता से आवेदन का निपटान करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए अपीलकर्ता देर से ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित कर सकता है. धारा 18 अपीलीय अधिकरण में अपील करने का प्रावधान करती है।

5) धारा 34 में कहा गया है कि किसी सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा

किसी ऐसे मामले के संबंध में किसी वाद या कार्यवाही पर विचार करना, जिसे निर्धारित करने के लिए अधिकरण या अपीलीय अधिकरण को शक्ति प्राप्त है। इसमें आगे कहा गया है कि सरफेसी अधिनियम या डीआरटी अधिनियम के तहत की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। सरफेसी अधिनियम की धारा 35 काफी हद तक डीआरटी

अधिनियम की धारा 34 (1) के समान है। यह घोषणा करता है कि इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे, इसके बावजूद कि किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत है या ऐसे किसी भी कानून के आधार पर प्रभावी है।

17) इसके अतिरिक्त, विभिन्न सांविधिक दृष्टिकोणों की जांच करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा रिट याचिकाओं की विचारणीयता से संबंधित सिद्धांतों को निर्धारित करने के कतिपय निर्णयों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। याचिका में मुद्दा इस बात से संबंधित नहीं है कि क्या प्रतिवादी-बैंक

यह संविधान के अनुच्छेद 12 में यथा परिभाषित "राज्य" के अर्थ के अंतर्गत आता है या राज्य का साधन है या नहीं। मूल प्रश्न यह है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर "किसी भी व्यक्ति" के खिलाफ विचार किया जा सकता है, जो प्रदर्शन करने के लिए वैधानिक दायित्व के तहत है, जहां दावा की गई राहत आवश्यक रूप से "राज्य", "सरकार" या "प्राधिकरण" या "राज्य के साधन" के खिलाफ नहीं है। प्रागा **टूल्स कॉरपोरेशन बनाम सीवी 1 मैनुअल और अन्य (11) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा** कि रिट याचिका किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के खिलाफ सक्षम होगी, जिस पर वैधानिक कर्तव्य लगाया गया है। इसे इस प्रकार देखा गया: -

> ".....हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति या प्राधिकरण पर वैधानिक कर्तव्य लगाया गया है, वह एक सार्वजनिक अधिकारी या एक आधिकारिक निकाय होना चाहिए। एक परमादेश जारी किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, एक मैं किसी सोसायटी का अधिकारी उसे उस क़ानून की शर्तों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए जिसके द्वारा सोसाइटी का गठन या शासन किया जाता है और कंपनियों या निगमों को भी उनके उपक्रमों को अधिकृत करने वाले क़ानूनों द्वारा उन पर लगाए गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मजबूर करना....."

18) ***)*** **श्री अनादि मुक्ता सद्गुरु श्री मुक्ताजेक वंदासजीस्वामी सुरवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट और अन्य बनाम वीआर रुदानी और अन्य *(12)* में, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित शब्दों में सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया: -**

> "19. अनुच्छेद 226 में प्रयुक्त शब्द "प्राधिकरण", संदर्भ में, आर्टियेल्क 12 शब्द के विपरीत एक उदार अर्थ प्राप्त करना चाहिए। अनुच्छेद 12 केवल अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उद्देश्य से प्रासंगिक है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ गैर-मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इली शब्द <
>
> इसलिए, अनुच्छेद 226 में प्रयुक्त "कोई व्यक्ति या प्राधिकरण" केवल राज्य के वैधानिक प्राधिकरणों और साधनों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। वे सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को कवर कर सकते हैं। मरने वाले शरीर का फोम चिंतित है

(11) एआईआर 1969 एससी 1306
(12) एआईआर 1989 एससी 1607

बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं है। जो प्रासंगिक है वह शरीर पर लगाए गए कर्तव्य की प्रकृति है। कर्तव्य को प्रभावित पक्ष के लिए व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा देय सकारात्मक दायित्व के प्रकाश में आंका जाना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस माध्यम से कर्तव्य लगाया जाता है। यदि कोई सकारात्मक दायित्व मौजूद है, तो परमादेश से इनकार नहीं किया जा सकता है।

आगे यह देखा गया कि -

"21. यहाँ फिर से हम यह बता सकते हैं कि परमादेश को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि लागू किया जाने वाला कर्तव्य क़ानून द्वारा अधिरोपित नहीं है। इस कानून के विकास पर टिप्पणी करते हुए, प्रोफेसर डी स्मिथ कहते हैं: "परमादेश द्वारा लागू करने योग्य होने के लिए एक सार्वजनिक कर्तव्य जरूरी नहीं कि क़ानून द्वारा लगाया गया हो। यह चार्टर, सामान्य कानून, कस्टम या यहां तक कि अनुबंध द्वारा लगाए गए कर्तव्य के लिए पर्याप्त हो सकता है। (प्रशासनिक की न्यायिक समीक्षा, 'अधिनियम, 4 वां संस्करण, पृष्ठ 540)। हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं। लोगों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निकायों के तेजी से फैलते चक्रव्यूह पर न्यायिक नियंत्रण को निर्विवाद डिब्बे में नहीं रखा जाना चाहिए। परिवर्तनशील परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे लचीला रहना चाहिए। परमादेश एक बहुत व्यापक उपाय है जो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए 'जहां भी अन्याय पाया जाता है' तक पहुंचने के लिए। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राहत प्रदान करने में तकनीकी बाधक नहीं बनना चाहिए। इसलिए, हम रिट याचिका की विचारणीयता पर अपीलकर्ताओं के लिए आग्रह किए गए तर्क को खारिज करते हैं।

(19) सुप्रीम कोर्ट ने वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड **बनाम** वीएसटी इंडस्ट्रीज वर्कर्स यूनियन (13) **में अनादि मुक्ता के मामले *(सुप्रा)* में अपने फैसले को और स्पष्ट करते हुए** निम्नानुसार देखा: -

"तानानादि मुक्ता मामले में, इस न्यायालय ने विभिन्न पहलुओं और एक प्राधिकारी और एक व्यक्ति के बीच अंतर की जांच की और उस संबंध में संदर्भित निर्णयों के विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह केवल उन परिस्थितियों में है जब प्राधिकरण या व्यक्ति सार्वजनिक कार्य करता है या सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करता है कि संविधान के अनुच्छेद 226 को लागू किया जा सकता है।

(13) (2001) 1 एससीसी 298

(20) उच्च न्यायालय, बिन्नी लिमिटेड और अन्य **बनाम एन में उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग के दायरे को परिभाषित करना।सदाशिवन और अन्य (14),** इस प्रकार नोट किए गए: -

"9. न्यायिक समीक्षा के सुपीरियर कोर्ट के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार को असंख्य मामलों में एक पीड़ित पक्ष द्वारा लागू किया जाता है। भारत में उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रशासनिक निर्णयों को सही करने के लिए न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है और इस अधिकार क्षेत्र के तहत उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को धारा 111 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई निर्देश या आदेश या रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त क्षेत्राधिकार बहुत व्यापक है। हालांकि, यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि यह एक सार्वजनिक कानून उपाय है और यह सार्वजनिक कानून कार्य करने वाले निकाय या व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध है। कुछ अंग्रेजी निर्णयों के आलोक में सार्वजनिक कानून के उपाय के दायरे और दायरे पर विचार करने से पहले, द्वारकानाथ बनाम आयकर अधिकारी 1965 (3) एससीआर 536 में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में व्यक्त सुभा राव जे के शब्दों को पृष्ठ 540-41 पर याद रखना उचित है:

"यह अनुच्छेद व्यापक वाक्यांशविज्ञान में लिखा गया है और यह उच्च न्यायालयों को अन्याय तक पहुंचने के लिए एक व्यापक शक्ति प्रदान करता है जहां भी यह पाया जाता है। संविधान ने शक्ति की प्रकृति, उद्देश्य और उस व्यक्ति या प्राधिकारी का वर्णन करने में एक व्यापक भाषा का उपयोग किया है जिसके खिलाफ इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह इंग्लैंड में समझे जाने वाले विशेषाधिकार रिट की प्रकृति में रिट जारी कर सकता है; लेकिन उन रिटों का दायरा भी "प्रकृति" अभिव्यक्ति के उपयोग से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उक्त अभिव्यक्ति डॉक्स भारत में जारी की जा सकने वाली रिटों की इंग्लैंड के साथ बराबरी नहीं करती है, लेकिन केवल उनसे एक सादृश्य खींचती है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय विशेषाधिकार रिट के अलावा अन्य निर्देश, आदेश या रिट भी जारी कर सकते हैं। यह उच्च न्यायालय को इस देश की विशिष्ट और जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राहतों को ढालने में सक्षम बनाता है। बराबरी करने का कोई भी प्रयास

(14) (2005) 6 एससीसी 657

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय को अंग्रेजी न्यायालयों के साथ विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति का दायरा इंग्लैंड जैसे अपेक्षाकृत छोटे देश में, जिसका सरकार का एकात्मक रूप है, वर्षों से विकसित अनावश्यक प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों को संघीय ढांचे के अधीन कार्य कर रहे भारत जैसे विशाल देश में लागू करना है। ऐसा निर्माण लेख के उद्देश्य को ही हरा देता है।

यह निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया था: -

"29. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि परमादेश का रिट या अनुच्छेद 226 के तहत उपाय पूर्व-प्रमुख रूप से एक सार्वजनिक कानून उपाय है और आम तौर पर निजी गलतियों के खिलाफ एक उपाय के रूप में उपलब्ध नहीं है। इसका उपयोग जनता के विभिन्न अधिकारों को लागू करने या सार्वजनिक/वैधानिक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और उनकी सीमा के भीतर कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग न्याय करने के लिए किया जा सकता है जब शक्ति का गलत प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करने से इनकार किया जाता है। यह रिट प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के रूप में काम करने के लिए सराहनीय रूप से सुसज्जित है। यह रिट किसी भी निजी निकाय या व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 226 में इस्तेमाल किए गए शब्दों को देखते हुए। हालांकि, परमादेश का दायरा सार्वजनिक कर्तव्य के प्रवर्तन तक सीमित है। परमादेश का दायरा उस प्राधिकारी की पहचान के बजाय लागू किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति से निर्धारित होता है, जिसके खिलाफ इसकी मांग की जाती है। यदि निजी निकाय किसी सार्वजनिक कार्य का निर्वहन कर रहा है और किसी भी अधिकार से वंचित करना ऐसे निकाय पर लगाए गए सार्वजनिक कर्तव्य के संबंध में है, तो सार्वजनिक कानून उपाय लागू किया जा सकता है। सार्वजनिक निकाय पर डाला गया कर्तव्य या तो वैधानिक या अन्यथा हो सकता है और ऐसी शक्ति का स्रोत सारहीन है, लेकिन, फिर भी, इस तरह की कार्रवाई में सार्वजनिक कानून तत्व होना चाहिए। कभी-कभी, सार्वजनिक कानून और निजी कानून उपायों के बीच अंतर करना मुश्किल होता है। इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानून के अनुसार, तीसरा संस्करण। खंड 30, पृष्ठ -682, "एक सार्वजनिक प्राधिकरण एक निकाय है जो जरूरी नहीं कि एक काउंटी परिषद, नगर निगम या अन्य स्थानीय प्राधिकरण है, जिसके पास प्रदर्शन करने के लिए सार्वजनिक वैधानिक कर्तव्य हैं और जो कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने लेनदेन करते हैं

जनता का लाभ और निजी लाभ के लिए नहीं। सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक कार्रवाई की कोई सामान्य परिभाषा नहीं हो सकती है।
प्रत्येक मामले के तथ्य बिंदु तय करते हैं। «

(21) मिस रवांक कौर **बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ**

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना (15) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के दायरे में तल्लीन करते हुए और उसके पैरा 59 में 'विशेषाधिकार रिट' जारी करते हुए संक्षेप में कहा था: -

"59. उपरोक्त के मद्देनजर, हम मानते हैं कि: - (i) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियां इंग्लैंड में किंग्स बेंच के न्यायालय की तुलना में व्यापक हैं।

(2) उच्च न्यायालयों की शक्ति मुद्दे तक ही सीमित नहीं है
विशेषाधिकार रिट के रूप में शुरू में इंग्लैंड में समझा जाता है। वही ^
इंग्लैंड में न्यायालयों पर लगाए गए प्रक्रियात्मक प्रतिबंध इस देश के उच्च न्यायालयों को बाध्य नहीं करते हैं। उच्च न्यायालयों को न केवल उत्प्रेषण, परमादेश आदि की प्रकृति में रिट जारी करने का अधिकार है, बल्कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश और निर्देश भी जारी करने का अधिकार है
या किसी अन्य उद्देश्य के लिए। 1

(3) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत शक्ति जैसे मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तक ही सीमित नहीं है। इससे भी आगे, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने वाले किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को रिट, आदेश या निर्देश जारी कर सकते हैं।

(4) अनुच्छेद 226 में प्रयुक्त शब्द "कोई व्यक्ति या प्राधिकरण" का अर्थ केवल अनुच्छेद 12 या वैधानिक प्राधिकरणों में परिभाषित राज्य नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति या निकाय को कवर करते हैं जो जनता को विधिवत रूप से प्रभावित करता है। 1

(5) समुदाय के लिए 'स्वास्थ्य' के महत्व को देखते हुए, चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान एक अलग वर्ग बनाते हैं। ये संस्थान एक सार्वजनिक कर्तव्य निभाते हैं और राज्य के प्रयास के पूरक हैं। किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य वैधानिक परीक्षा निकाय से उनकी संबद्धता से, वे

राज्य के साथ भागीदार बनें। अत यह भाग III में निहित प्रतिबंधों के अध्यधीन है। वे भारतीय आयुवज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के उपबंधों और उपयुक्त विश्वविद्यालय/निकाय द्वारा बनाए गए नियमों/नियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हैं। जब कभी वे संविधान के भाग-3 में अंतवष्ट निषेधों अथवा

(15) (!997)2PLR320

विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों आदि के अनुचित, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं या उनका उल्लंघन करते हैं तो उनके कार्यों को उत्प्रेषण रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निदेश जारी करके ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि यह पाया जाता है कि कोई संस्था संविधान के तहत किसी दायित्व को पूरा करने में विफल रही है या किसी उपयुक्त निकाय द्वारा तैयार किए गए नियम/नियम/विनियम को पूरा करने में विफल रही है, तो उसे परमादेश रिट जारी करके अपना कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हालांकि, यह सिद्धांत हर निजी स्कूल या कॉलेज के मामले में लागू नहीं होगा।

(6) प्रीतम सिंह बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय। पंजाब राज्य, (1982) 2 ScrvLR 135: (AIR 1982 Punj & har 228) और गुरप्रीत सिंह सिंधु v. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, एआईआर 1983 पुंज और हर 70, में कानून और आर्कोवक्रलक्ड का सही प्रतिपादन नहीं है।

(22) **फिरोजाली अब्दुलकरीम जिवानी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (16) में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने** फ्रैगा टूल्स कॉरपोरेशन के मामले (सुप्रा) **में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन** करते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निजी व्यक्ति के खिलाफ रिट कानून द्वारा उन पर लगाए गए कर्तव्यों और दायित्वों के प्रवर्तन के लिए जारी की जा सकती है। पैरा 25 में की गई टिप्पणियां जो प्रासंगिक हैं, इस प्रकार पढ़ें: -

"25. हमें इस प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या प्रतिवादी नंबर 6 बैंक अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक 'राज्य' है। वर्तमान मामले में, जो लागू करने की मांग की गई है, वह प्रतिवादी नंबर 6 बैंक और उसके रिटर्निंग अधिकारी प्रतिवादी नंबर 7 पर एस के प्रावधानों के आधार पर लगाया गया वैधानिक कर्तव्य है। 37. यह सच है कि रिटर्निंग अधिकारी भी एक निजी व्यक्ति है,

क्योंकि प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा बनाए गए निदेशक मंडल के सदस्यों के चुनाव के संबंध में नियमों में, निदेशक मंडल द्वारा एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक है। ,
फिर भी, अधिनियम में रिटर्निंग अधिकारी के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 10 पर कुछ सांविधिक कर्तव्यों और बाध्यताओं का प्रावधान किया गया है।
6. इन वैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों के प्रवर्तन के लिए, एक रिट झूठ होगी। जैसा कि PragaToolsCorpn के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखा गया था। वि० [सं०] [वि० स्त्री० इमैनुअल]

".....हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति या प्राधिकरण पर वैधानिक कर्तव्य लगाया गया है, वह सार्वजनिक अधिकारी या आधिकारिक निकाय हो। उदाहरण के लिए, एक परमादेश

(16) एआईआर 1992 बॉम्बे 179

जारी किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, एक समाज के एक अधिकारी को जारी किया जा सकता है ताकि उसे उस क़ानून के दसियों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सके जिसके तहत या जिसके द्वारा समाज का गठन या शासित किया जाता है और कंपनियों या निगमों को भी उनके उपक्रमों को अधिकृत करने वाले कानूनों द्वारा उन पर लगाए गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए....."(पृष्ठ 1309)।

इसलिए, एक रिट बनाए रखने योग्य है।

(23) (क) में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ **राहुल मेहरा बनाम** ^ **(ग) भारत संघ (17**) ने अनादि मु क, वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फेडरल बैंक लिमिटेड **के मामलों (सुप्रा) में टीएचसीएपीसीएक्स न्यायालय के निर्णयों के आलोक में**, इस मुद्दे पर निर्णय लेते हुए कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी था, ने देखा था कि उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, आदेश या * मैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी मौलिक अधिकार के लिए या "किसी अन्य उद्देश्य के लिए" निर्देश देता हूं, यहां तक कि जहां राज्य विवाद में सीधे शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन मुद्दा सार्वजनिक कर्तव्य या निजी निकाय द्वारा सार्वजनिक कार्य के प्रदर्शन का है। इसे इस प्रकार देखा गया: -

उन्होंने कहा, 'इसलिए मुख्य सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है? उप-अनुच्छेद (1) निम्नानुसार पढ़ता है: -

"226. उच्च न्यायालयों की शक्ति 1'0 कुछ डब्ल्यूआर जारी करता है। (1) अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक न्यायालय को सभी राज्यक्षेत्रों में शक्तियाँ होंगी

(16) एआईआर 1992 बॉम्बे 179

जिसके संबंध में यह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को, जिसमें उपयुक्त मामलों में, कोई भी सरकार शामिल है, उन क्षेत्रों के भीतर निर्देश, आदेश या रिट जारी करना, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंट और उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट शामिल हैं, या उनमें से कोई भी, भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

xxxx xxxx xxxx xxxx xxx"

एक सादा पढ़ने से पता चलता है कि शक्तियां पूर्ण हैं और उच्च न्यायालय किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए और "किसी भी तेल के उद्देश्य के लिए" किसी भी व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है। हालांकि, इन व्यापक शक्तियों को न्यायिक घोषणाओं द्वारा विनियमित किया गया है ताकि उन मामलों में हस्तक्षेप से बचा जा सके जहां वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं और जहां विवाद विशुद्ध रूप से एक निजी प्राकृतिक "सार्वजनिक कानून" तत्व का है। पारंपरिक दृष्टिकोण यह था कि जहां भी राज्य या उसके साधन शामिल थे, इसे सार्वजनिक कानून के क्षेत्र के भीतर एक मुद्दा माना जाता था। इसी तरह, जहां व्यक्ति लॉगरहेड्स में थे, उपाय निजी कानून के परिसर के भीतर था। यह सब तब तक बहुत अच्छा था जब तक शासन शासन से चिपके रहे और निजी व्यक्तियों या निकायों ने अपनी गतिविधियों को निजी प्रकृति के कार्यों तक सीमित रखा। लेकिन, जब राज्य ने वाणिज्य, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश किया और जब निजी निकायों ने सार्वजनिक कार्यों और कर्तव्यों को संभाला, तो संस्था के सार्वजनिक या निजी चरित्र के आधार पर सार्वजनिक कानून और निजी कानून के बीच यह अंतर अब स्पष्ट नहीं था। इसलिए, यह तय करने के लिए पूरी तरह से संस्था के चरित्र पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं था कि यह रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी था या नहीं। उदाहरण के लिए, जहां विशुद्ध रूप से संविदात्मक प्रकृति का विवाद है (वैधानिक अनुबंध नहीं है), इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टियों में से एक "राज्य" या "वैधानिक निकाय" या "राज्य का साधन" है, ऐसा मामला निजी कानून के क्षेत्र में आता है और अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा झूठ नहीं होगी। और

बातचीत भी उतनी ही सच होगी। दूसरे शब्दों में, एक विवाद जिसमें राज्य सीधे शामिल नहीं है, फिर भी एक सार्वजनिक कानून मुद्दा हो सकता है यदि एक सार्वजनिक कर्तव्य या सार्वजनिक कार्य एक निजी निकाय द्वारा किया जाता है।

8. सरकारों ने निजी क्षेत्र में कदम रखा है और निजी निकायों ने भी सार्वजनिक कर्तव्यों या सार्वजनिक कार्यों को अंजाम दिया है। ओवरलैप की एक डिग्री है और भेद अब स्पष्ट-कट या वाटरटाइट नहीं है। कानून को इन गतिकी के लिए जीवित होना चाहिए। तदनुसार, रिट याचिका की विचारणीयता के प्रश्न को सुगम्यता के दृष्टिकोण से संबोधित

नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के प्रति उत्तरदायी है। तथापि, न्यायालयों ने संयम बरता है और वे इन शक्तियों का प्रयोग केवल उन्हीं मामलों में करते हैं जिनमें लोक कानून अंतर्वलित होता है। इसलिए, रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए "लिटमस" परीक्षण यह है कि क्या शिकायत की गई अधिनियम सार्वजनिक कर्तव्य या सार्वजनिक कार्य के निर्वहन में है। यह बहुत कम मायने रखता है कि कौन सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करता है या सार्वजनिक कार्य करता है। और इसलिए भी, इस तरह के कर्तव्य या कार्य का निर्वहन या प्रदर्शन करने की शक्ति का स्रोत। क्या व्यक्ति को क़ानून या कुछ सरकारी आदेश द्वारा सशक्त किया गया है या क्या ऐसा व्यक्ति खुद को सार्वजनिक कार्य करने या सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने की शक्ति का दावा करता है, इसका कोई मतलब नहीं है। यह देखा जाना चाहिए कि क्या इस तरह के कर्तव्य या कार्य के निर्वहन में कोई उल्लंघन होता है। यदि ऐसा है तो उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति को आदेश, निदेश या रिट जारी करके इसे ठीक करने की शक्ति है। फंडिंग भी कोई मुद्दा नहीं है। एक निजी वित्त पोषित निजी संगठन लेकिन सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करना अभी भी अनुच्छेद 226 के "जाल" के भीतर होगा।

(24) निष्कर्ष को सारांशित करते हुए, ii था: -

"17. पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम कह सकते हैं कि संपूर्ण "अक्षमता" मुद्दा गलत है। एक निकाय, सार्वजनिक या निजी, को रिट क्षेत्राधिकार के लिए "आदम्य" या "स्वीकार्य नहीं" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। "फ़ंक्शन" परीक्षण परीक्षण करने के लिए सही है

रखरखाव। यदि कोई सार्वजनिक कर्तव्य या सार्वजनिक कार्य शामिल है, तो कोई भी निकाय, सार्वजनिक या निजी, उस कर्तव्य या कार्य के लिए, और उस तक सीमित, के तहत न्यायिक जांच के अधीन होगा

अनुच्छेद 226 का असाधारण रिट क्षेत्राधिकार। बीसीसीआई जो भारत में क्रिकेट की हर चीज का एकमात्र भंडार है, ने अपने संगठन, कौशल, भारत में खेल के लिए दीवानगी और सरकार की मौन स्वीकृति के माध्यम से इस "विशाल" कद को प्राप्त किया है। इसकी वस्तुएं वे कार्य और कर्तव्य हैं जिन्हें इसने स्वयं पर अहंकार किया है। इनमें से कई सार्वजनिक कर्तव्यों और कार्यों की प्रकृति में हैं। अन्य निजी कानून के क्षेत्र में हो सकते हैं जैसे कि निजी अनुबंध, आंतरिक नियम जो बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित नहीं करते हैं आदि। इसलिए, बीसीसीआई को आने वाले समय में सभी स्थितियों में अनुच्छेद 226 के दायरे से बाहर नहीं कहा जा सकता है। बीसीसीआई इस अदालत से यही प्रमाण पत्र चाहता है। हमें डर है, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। नतीजतन, इस याचिका को रखरखाव के मुद्दे पर खारिज नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता उन आदेशों, निर्देशों या रिटों के हकदार होंगे जो वे चाहते हैं। गुण-दोष के आधार पर इसकी जांच करनी होगी।

(25) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने **फेडरल बैंक मामले *(सुप्रा)* में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया था** जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका की विचारणीयता से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों को मोटे तौर पर निर्धारित किया था: -

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका (i) राज्य सरकार के खिलाफ सुनवाई योग्य हो सकती है; (ii) एक प्राधिकरण; (iii) एक सांविधिक निकाय; (iv) राज्य का एक साधन या एजेंसी; (v) एक कंपनी जो राज्य द्वारा वित्तपोषित और स्वामित्व में है; (vi) एक निजी निकाय जो पर्याप्त रूप से राज्य वित्त पोषण पर चलता है; (vii) सार्वजनिक प्रकृति के सार्वजनिक कर्तव्य या दायित्व का निर्वहन करने वाला कोई निजी निकाय; और (viii) किसी भी क़ानून के तहत किसी भी कार्य का निर्वहन करने के लिए एक व्यक्ति या एक निकाय के तहत, इसे इस तरह के वैधानिक कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाले किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को प्रभावित पक्ष के प्रति सकारात्मक दायित्व के कारण परमादेश जारी किया जा सकता है।

यह आगे निम्नानुसार देखा गया: -

"27. ऐसी निजी कंपनियां आम तौर पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसे निजी निकायों या व्यक्तियों को एक रिट जारी की जा सकती है क्योंकि ऐसी विधियां हो सकती हैं जिनका निजी कंपनियों सहित सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक

विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना अधिनियम या उचित पर्यावरण बनाए रखने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 या जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 आदि जैसे कुछ कानून या इसी तरह की प्रकृति की विधियां हैं जो ऐसे निजी निकायों पर वैधानिक रूप से कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बांधती हैं जिनका वे अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं। यदि वे इस तरह के वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो निश्चित रूप से उन प्रावधानों के अनुपालन के लिए एक रिट जारी की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई निजी नियोक्ता औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारी की सेवा से वंचित करता है, तो असंख्य मामलों में उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और निजी निकायों और कंपनियों को इस संबंध में रिट जारी की है। लेकिन रिट जारी करने में कठिनाई तब उत्पन्न हो सकती है जब निजी निकाय द्वारा किसी वैधानिक प्रावधान का कोई गैर-अनुपालन या उल्लंघन नहीं हो सकता है। उस स्थिति में एक रिट बिल्कुल भी जारी नहीं की जा सकती है। अन्य उपाय, जो भी उपलब्ध हो सकते हैं, का सहारा लेना पड़ सकता है।

(26) एक अन्य कारक जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत, बैंक की कार्रवाई के खिलाफ ऋण वसूली न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है और इसके तहत पारित किसी भी आदेश के खिलाफ, उक्त अधिनियम की धारा 18 के तहत ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) में अपील सुनवाई योग्य है। DRAT द्वारा पारित आदेश उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है। इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित मुद्दे को तय करने में सरफेसी अधिनियम की धारा 34 का भी महत्व है। इलिस पहलू यहां उठाए गए विवाद को अलग आयाम देता है। धारा 34 उन कार्यों से संबंधित मामलों में सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है जहां सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है। संविधान गारंटी देता है

समानता और किसी प्राधिकरण की किसी भी मनमानी कार्रवाई के खिलाफ हमला। यह नहीं कहा जा सकता है कि जहां भी कोई प्राधिकारी भेदभावपूर्ण या अनुचित तरीके से कार्य करता है, पीड़ित पक्ष के पास सिविल सूट के माध्यम से या उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करके कोई उपाय नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता है कि अनुसूचित बैंक द्वारा एक कार्रवाई, जिस पर सरफेसी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं और इसके द्वारा लागू किए गए हैं, यह इस न्यायालय के असाधारण रिट क्षेत्राधिकार से प्रतिरक्षा होगी।

(27) अब उन मामलों का विज्ञापन करते हुए, जिन पर प्रतिवादी-बैंक के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया था, **फेडरल बैंक के** मामले (सुप्रा) में प्रश्न नियोक्ता-कर्मचारी विवाद से संबंधित था, जिसके लिए कर्मचारी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए रिट कोर्ट से संपर्क करने की मांग की थी। यह उन परिस्थितियों में था, यह माना गया था कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। हालांकि, **सत्यवती टंडानंद तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड** (सुप्रा) के मामले तथ्यों पर अलग-अलग होने के कारण उत्तरदाताओं के मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं।

(28) उपर्युक्त से, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आमतौर पर कोई भी रिट निजी बैंक के खिलाफ नहीं होगी। हालांकि, जहां बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत एक अनुसूचित बैंक है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों द्वारा शासित है, यह इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी होगा जहां अनुसूचित बैंक सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेता है।

(29) अब संख्या (ख) और (ग) में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को लेते हुए, उन पर एक साथ निर्णय लिया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी बैंक को ओटीएस के लिए <i प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को 22.3.2011 तक बकाया देयता को समाप्त करने की आवश्यकता थी जो अवधि दिनांक 18.4.2011 के पत्र द्वारा बढ़ा दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने 50,00,000/- रुपये जमा किए थे और बैंक द्वारा स्वीकृत ओटीएस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शेष 2 करोड़ रुपये जमा किए जाने थे। कुछ व्यक्तिगत और व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण याचिकाकर्ता प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं कर सके और आगे विस्तार की मांग की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। 17.6.2011 को याचिकाकर्ता नंबर 2 और 3 के पिता बीमार होने के बाद

एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने 2 करोड़ रुपये की शेष बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी बैंक से पुन संपर्क किया। बैंक ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी सदाशयता दिखाने के लिए 26.7.2011 को बैंक को 2 करोड़ रुपये के ड्राफ्ट प्रस्तुत किए थे और 10.2.2012 को इस न्यायालय में विधिवत पुनर्वैधीकृत चार मांग-ड्राफ्ट भी पेश किए थे जिन्हें इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पास जमा किया गया था। इसके अलावा, 25.7.2012 को, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा था कि 2 करोड़ रुपये की उपरोक्त राशि के अलावा, याचिकाकर्ता 50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए तैयार थे। रईस का इरादा स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं की सदाशयता को दर्शाता है। इससे पहले देखी गई घटनाओं के वर्णन से पता चलता है कि यह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण अनिवार्यताओं के कारण था, याचिकाकर्ता ओ'आई की शर्तों का सम्मान नहीं कर सके। ऐसी परिस्थितियों में, ओटीएस को अस्वीकार करने में प्रतिवादी-बैंक की कार्रवाई कठोर और अन्यायपूर्ण है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के पास ओटीएस प्रस्ताव के लिए समय के विस्तार की अस्वीकृति के खिलाफ कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है। **सत करतार आइस एंड जनरल मिल्स बनाम पंजाब फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (18)** मामले में इस अदालत ने ओटीएस की राशि जमा करने में देरी को माफ कर दिया था और बैंक को ओटीएस का पालन करने का निर्देश दिया था। इसी प्रकार, **भारतीय स्टेट बैंक** बनाम **विजय कुमार (19)** के मामले में पुन उच्च न्यायालय द्वारा माफ की गई राशि को जमा करने में विलंब को उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया था। तद्नुसार, रिट याचिका को स्वीकार करते समय राशि जमा करने में विलंब को माफ करने के बाद वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में यह निदेश दिया जाता है कि मामले में याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो माह के भीतर 25002012 को उनके वकील द्वारा दिए गए बयान के अनुसार 50 लाख रुपये की एक और राशि जमा कराएं। ओटीएस लागू किया जाएगा। यह भी निदेश दिया जाता है कि इस न्यायालय के दिनांक 10.02.2012 के आदेश के अनुसरण में जमा किए गए मसौदे

याचिकाकर्ताओं को लौटा दिए जाएंगे, जो उन्हें पुन वैधीकृत कराने के बाद, ओटीएस लागू कराने के लिए उपर्युक्त अवधि के भीतर बैंक में जमा करेंगे।

(30) उपर्युक्त के मद्देनजर, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

/मैं। जैनी

(18) 2OO8(1)1SJ बैंकिंग 248
(19) एआईआर 2007 एससी 1689

*2434/*एचसी आईएलआर-गवर्नमेंट प्रेस, यूटी, सीएचडी।

अस्वीकरण*:* स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |

जैस्मिन प्रीत कौर

प्रक्षिशु न्यायिक अधिकारी

सोनीपत
हरियाणा